खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यकरण के संबंध में समिति

3980. **श्री बीरेन जे० शाह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यकरण पर पुनर्विचार करने के लिए 1993 में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों के नाम क्या क्या हैं और इस समिति को सौंपे गये कार्य का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य मुख्य बातें क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो रिपोर्ट सौंपने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने प्राप्त हुई रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए आयोग के कार्यकरण को प्रभावी बनाने के लिए कोई कार्य योजना बनायी है; और

(च) यदि हां, तो उक्त कार्य योजना का ब्योरा क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति का गठन और उसके विचारणीय विषय विवरण में दिये गये हैं । (नीचे देखिये)

(ग) जी, नहीं ।

(घ) रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है । इसे शीघ्र प्रस्तुत किया जायेगा ।

(ङ) और (च) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन :

1. प्रधान मंत्री . . . अध्यक्ष
2. श्री ए० के० एंटोनी, . . नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता कार्य और कार्यकारी सार्वजनिक वितरण मंत्री . अध्यक्ष
3. वित्त मंत्री . . . सदस्य
4. उपाध्यक्ष, योजना आयोग . सदस्य
5. राज्य मंत्री (ल० उ० तथा कृषि एवं ग्रा० उद्योग) सदस्य
6. राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास) . सदस्य
7. राज्य मंत्री (श्रम) . . सदस्य
8. श्री नवल किशोर शर्मा, महासचिव, ए० आई० सी० सी० (आई०) . सदस्य
9. श्री बासविजय, संयोजक, खादी मिशन, गोपुरी, वर्धा . सदस्य
10. श्री सोमदत्त, पूर्व अध्यक्ष, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग तथा सचिव, खादी आश्रम, पानीपत (हरियाणा) . सदस्य
11. श्री वी० रामचंद्रन, पूर्व सदस्य-सचिव, भारतीय ग्रामोद्योग (दक्षिण), कोयम्बतूर सदस्य
12. श्रीमती जया बहन शाह, अध्यक्ष, सौराष्ट्र रचनात्मक समिति, राजकोट . सदस्य
13. श्री एल० के० बंदोपाध्याय, सचिव, गांधी स्मारक निधि और पूर्व-सदस्य, खादी ग्रामोद्योग आयोग सदस्य
14. श्री अवधेश सिंह, सचिव, गांधी आश्रम, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश . सदस्य
15. श्रीमती लेंसिना ठक्कर, नागालैंड गांधी आश्रम, पो०औ० चुचिमबंग, कोहिमा (नागालैंड) . . सदस्य
16. अध्यक्ष, के० वी० आई० सी० . सदस्य
17. श्रीमती मोहसिना किडवई . सदस्य
18. श्री मनुभाई मेहता . . सदस्य
19. श्री लक्ष्मी दास, पूर्व-अध्यक्ष, के० वी० आई सी० . सदस्य
20. सचिव, (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग) . . . सदस्य

विचारणीय विषय :

1. खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र की निरंतर वृद्धि और विकास हेतु उचित नीतिगत सहायता (आरक्षण सहित) की जांच तथा उपाय सुझाना ।

2. इस क्षेत्र में सरकार द्वारा निवेश बढ़ाने के लिए उपाय सुझाना और उक्त आयोग वित्तीय संस्थानों और बैंकों से पर्याप्त मात्रा में तथा समय से ऋण प्राप्त करना सुनिश्चित करना ।

3. पर्याप्त कच्चा माल, विपणन सहायता और अन्य सुविधाओं की आपूर्ति के लिए उपाय सुझाना ।

4. प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए मौजूदा अधः-संरचना की जांच तथा कारीगरों, पर्यवेक्षी स्टाफ,

प्रबंधकीय कार्मिकों तथा प्रवर्तक संबंधी कार्यों में लगे व्यक्तियों की सहायता के लिए ऐसी सुविधाओं में सुधार करने के उपाय सुझाना ।

5. अनुसंधान तथा और आधुनिकीकरण की दिशा में उपाय सुझाना और उत्पादकता के स्वरूप और विशेष सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त तकनॉलाजी को अपनाना ताकि उत्पादकता में वृद्धि हो सके ।

6. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग और खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की पुनःसंरचना के लिए उपाय सुझाना ताकि ये संगठन अपने कार्यों का निष्पादन अधिक विकेन्द्रित तथा कारगर ढंग से कर सकें ।

7. अधिक लोगों की भागीदारी हासिल करने के लिए और खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र, पंचायत राज संस्थानों व अन्य अभिकरणों तथा ग्रामीण विकास से संबद्ध सरकारी विभागों के बीच प्रभावी तालमेल के उपाय सुझाना ।

8. इस बात की जांच करना कि किस सीमा तक व्यावसायिक तथा लाभ कमाने वाले संगठनों पर लागू मौजूदा श्रमिक कानूनों को के० वी० आई० संस्थानों पर लागू किया जाना चाहिए जिसके लिए इन संस्थानों द्वारा किये जाने वाले कार्यक्रमों के विशेष स्वरूप का ध्यान रखा जाना चाहिए ।

9. विषय से संबंधित कोई अन्य मामला ।

Public Sector Projects to Private Companies

3981. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a report published in the Economic Times of March 27, 1994 under the caption '36 Public Sector Projects to be offered to private companies';

(b) if so, what are the facts and the details of such projects; and

(c) what is the extent of annual loss suffered and the performance of each of these public sector projects during each of the last three years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The information is being collected and will be laid on the table of the House.

Clearance of foreign investment proposals

3982. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY:
SHRI G. G. SWELL:
SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE:
SHRI SARADA MOHANTY:
SHRI SOM PAL:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that since liberalisation, the Foreign Investment Promotion Board has so far cleared foreign investment proposals to the tune of Rs. 5,200 crores;

(b) if so, what is the actual inflow of capital and which are the sectors where it has flowed;

(c) whether it is also a fact that at State levels, controls are tighter and therefore fast inflow of foreign capital is hampered;

(d) if so, the details about the nature and scope of the controls of the States and Centre's attempts to relax them;

(e) how is it that China in the first half of 1993 could attract and approve foreign investment of about 58 billion dollar and actual inflow of 9 billion; and

(f) what are the differences between our terms and Chinese terms for attracting foreign investments?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) Since the announcement of New Industrial Policy, Govt. have issued approvals, on the recommendation of the Foreign Investment Promotion Board, to proposals envisaging total foreign direct investment of Rs. 11482.39 crores upto February, 1994.

(b) The RBI have reported that the actual inflow of foreign direct invesment from 1991 to February, 1994 is estimated at Rs. 3114.46 crores. Sector-wise break-up of the total actual inflow of foreign direct investment are not maintained by the RBI.

(c) and (d) Various entrepreneurs often complain in regards to the difficulties experienced by them in getting speedier environmental clearance from State Pollution Control Boards, sanction for power and other infrastructure facilities for setting up the projects at State level. It has been Govt.'s endeavour to constantly interact with State Governments with a view to simplify the various procedures and remove bottlenecks. The process of simplification/rationalisation of various rules and regulations at State level is an on-going process.

(e) and (f) Apart from having a distinct geographical and political set up, China has been in the race for attracting foreign